मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1114

10.02.2025 को उत्तर के लिए

मृदा खनन

1114. श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संघ राज्यक्षेत्र दीव में दीव हवाई अड्डे और फुदम गौशाला के पास मृदा का खनन किए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है और यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में जांच की जाएगी;

(ग) क्या सरकार ने उपरोक्त संपत्ति से मृदा खनन की स्वीकृति दे दी है;

(घ) यदि हां, तो आदेश की प्रति सहित उपर्युक्त संपत्ति से मृदा खनन से अर्जित रॉयल्टी आय की पूरी जानकारी देने वाले आदेश का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर स्वीकृति के लिए की-गई-कार्रवाई की सम्पूर्ण जानकारी क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री

(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ङ) दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव के संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, दीव हवाई अड्डे और फुदम गौशाला के निकट कोई मृदा खनन गतिविधि नहीं की गई है। दमन एवं दीव के उप वन संरक्षक ने भी रिपोर्ट दी है कि संघ राज्यक्षेत्र दीव में दीव हवाई अड्डे और फुदम गौशाला के निकट अधिसूचित वन क्षेत्र के अंदर मृदा खनन से संबंधित कोई घटना नहीं देखी गई है।

यूटी प्रशासन ने यह भी सूचित किया है कि दिनांक 31.01.2022, दिनांक 15.11.2022 और दिनांक 09.10.2023 को आयोजित एयरफील्ड पर्यावरण समिति (गृह मंत्रालय द्वारा जारी पत्र संख्या 53/1/80-सार्वजनिक दिनांक 7 मई, 1980 के अनुसार गठित) की बैठकों में, हवाई यातायात सेवा प्रभारी ने दीव हवाई अड्डे की चारदीवारी के साथ रेत डंपिंग के बारे में मुद्दा उठाया था और हवाई अड्डे की चारदीवारी से दूर रेत डंपिंग के लिए उपयुक्त स्थान का अनुरोध किया था क्योंकि यह बाहर से चारदीवारी की प्रभावी ऊंचाई को कम करके विमान संचालन के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहा था। हवाई यातायात सेवा प्रभारी द्वारा उठाई गई सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए और एयरफील्ड पर्यावरण समिति के अध्यक्ष अर्थात् कलेक्टर, दीव द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, हवाई अड्डे की चारदीवारी से रेत हटा दी गई है और इसका उपयोग लोक निर्माण विभाग द्वारा सरकारी परियोजना स्थलों की बैकफिलिंग के लिए किया गया है। फुदम गौशाला में, केवल गौशाला भूखंड का समतलीकरण किया गया है।

******